desirability of adopting a standard practice of specifying a single rate at which private' investors are asked to sell power. The Committee felt that adoption of a simple tariff system would also eliminate the need of offering guaranteed PLF linked return on equity.

(d) and (d) Setting up of private power projects normally comes under the realm of the State Governments. However, the Control Electricity Authority scruitinises the costs and tariffs of these projects and accords techno-economic clearance only when it is satisfied that the cost are reasonable.

बैंकों की रूग्ण उद्योगों में फंसी राशि

59. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीकृत बैंकों की बहुत बड़ी राशि देश के रूग्ण उद्योगों में फंसी हुई है,

(ख)यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान ऐसी कितनी-कितनी राशि अनुत्पादक कार्यों में फंसी हुई थी, और

(ग) अनुत्पादक क्षेत्र में फंसी हुई ऐसी राशि उपरोक्त प्रत्येक वर्ष के दौरान उद्योग के विस्तार एंव विकास के प्रयोजनार्थ बैंकों द्वारा दी गई कुल राशि का कितना-कितना प्रतिशत थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.) देवी प्रसाद पाला) : (क) से (ग)भारतीर्य रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैकों से प्राप्त हुए छमाही आंकड़ों इकाइयों पर, देश में रूग्ण/कमजोर औद्योगिक इकाइयों पर बकाया राशि और मार्च 1992, मार्च, 1993 और मार्च 1994 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार, उद्योग को कुल बकाया बैंक ऋण की तुलना में ऐसे बकाया की प्रतिशतता, निम्नकार थी :

(करोड़ रूपए)

के अन्त की स्थिति	बकाया राशि	उद्योग को कुल बैंक ऋण की तुलना में बकाया राशि की प्रतिशतता
मार्च,1992	11533.30	17.6
मार्च,1993	13134.44	16.7
मार्च,1994	13695.74	17.0

काले धन की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होना

60. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** :

श्री अनन्तराय जायसवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में काले धन की मात्रा हजारों करोड़ रूपये में हैं और वह राशि निरन्तर बढ़ रही है,

(ख) यदि हां, तो काले धन की यह राशि कुल कितनी है और काले धन की उक्त राशि की मात्रा में ज्यादातर राशि किस धंधे से पैदा होती है,और

(ग) क्या सरकार ने देश में तीव्र गति से बढ़ रहे काले धन की मात्रा पर अंकुश/रोक लगाने हेतु कोई ठोस कार्रवाई की है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और उसका क्या परिणाम रहा है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रेशखर मूर्ति): (क)और (ख) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान द्वारा 1983-84 में किए गए अध्ययन में 31584 करोड़ रू. से 36786 करोड़ रू. के बीच काले धन का अनुमान लगाया गया था । इसके बाद इस विषय पर कोई प्रमाणिक अध्ययन नहीं किया गया है और अतः काले धन की मात्रा को बनाना अथवा सर्वाधिक काले धन को पैदा करने वाले कारोबारों का पता लगाना संभव नहीं है ।

(ग) जी,हां । सरकार काले धन की वृद्धि को रोकने के लिए समय-समय पर जैसा भी आवश्यक समझा जाए, आवश्यक कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक उपाय करती आ रही है । कराधान की दरों को